मई 2020

1. उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है जो COVID-19 महामारी के बीच स्वास्थ्य संबंधी युक्तियों और आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।

- "मोबाइल ऐप आयुष कवच COVID-19 स्वास्थ्य संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश के आयुष विभाग द्वारा विकसित किया गया था।

2. उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी कामगारों को सहायता प्रदान करने के लिए R प्रवासीवासी मित्र 'शुरू किया है।

- नोट: मोबाइल एप्लिकेशन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) के सहयोग से राज्य के राजस्व विभाग द्वारा विकसित किया गया है।

3. उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ 800 किलोमीटर हर्बल रोड विकसित करने की घोषणा की।

- नोट: इन हर्बल सड़कों पर सड़क के दोनों ओर हर्बल और औषधीय पेड़ होंगे।

4. हर्बल सड़कों पर पेड़ों में पीपल, नीम, सहजन के साथ-साथ ब्राह्मी, अश्वगंधा और जटरोफा जैसे हर्बल पेड़ शामिल हैं।

gradeup

Gradeup UP State Exams Super Subscription | Access to all Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

5. उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार ने नागरिकों की खाद्य जरूरतों के लिए अन्नपूर्णा , आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किए।

- अन्नपूर्णा पोर्टल का उद्देश्य लोगों को खाद्य उत्पादों के अपने ज्ञान को बढ़ाने में मदद करना होगा जो उन्हें मिलता है। इसके अलावा , आपूर्ति मित्र पोर्टल etables की मुफ्त होम डिलीवरी प्रदान करेगा।

6. उत्तर प्रदेश सरकार 3 साल के लिए अधिकांश श्रम कानूनों को निलंबित करने के लिए अध्यादेश लाती है।

- राज्य सरकार का उद्देश्य औद्योगिक निवेश में वृद्धि करना है और प्रवासी श्रमिकों के रोजगार को बढ़ाना है जो यूपी में अपने पैतृक गांवों में वापस आ गए हैं।
- यूपी सरकार ने तदनुसार इस आशय का एक अध्यादेश पारित किया है जो सभी कारखानों और विनिर्माण सुविधाओं पर भी लागू होगा। राज्य में आने वाले नए निवेश।
- यह अध्यादेश कुछ कानूनों जैसे बंधुआ मजदूर अधिनियम , भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम , मजदूरी अधिनियम की धारा 5 और श्रमिक मुआवजा अधिनियम पर लागू नहीं होगा। बच्चों और महिलाओं से संबंधित श्रम कानून भी प्रभावित नहीं होंगे।
- अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य उद्योगों को स्वतंत्र रूप से प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित करना है जो यूपी में वापस आ गए हैं

gradeup

Gradeup UP State Exams Super Subscription | Access to all Structured Courses & Test Series ENROL NOW

7. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बुधवार को लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा प्रबंधित किए जाने वाले 'यूपी स्टार्ट-अप फंड' की शुरुआत की।

- फंड की स्थापना यूपी सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्ट-अप नीति 2017 के तहत की गई है।
- यूपी सरकार और सिडबी के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर के बीच, सीएम ने 15 करोड़ रुपये के प्रारंभिक योगदान का एक चेक सौंपा फंड की ओर।
- "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के कारण, स्टार्ट-अप संस्कृति भारत में बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पीएम युवाओं को नौकरी देने वाले के रूप में पेश करते हैं। आदित्यनाथ ने आगे उल्लेख किया कि यूपी में असीमित स्टार्ट-अप क्षमता थी और बड़े पैमाने पर नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, आईटी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में बड़े अवसरों की पेशकश की।

gradeup

Gradeup UP State Exams Super Subscription | Access to all Structured Courses & Test Series | ENROL NOW